

GST परिषद की 57वीं बैठक में सुधारों पर मंथन, कारोबारियों को राहत की आस



भारतार्थ खबर
Bhaarataraarth.com
संवाददाता अशोक कुमार सिंह
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर 2026 ।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)
व्यवस्था को सरल बनाने, कारोबारियों
की अनुपालन लागत घटाने और
कर प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के
मुद्दों पर जीएसटी परिषद की 57वीं
 बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा
हो रही है। नई दिल्ली स्थित भारत
मंडपम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला
सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित
इस बैठक से छोटे कारोबारियों और
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों
(एमएसएमई) को राहत मिलने की
उम्मीद जाई जा रही है। बैठक में
इमपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी),
जीएसटी रिफंड, पंजीकरण, रिसर्च
दाखिल करने की प्रक्रिया और कर
विवादों के समाधान को अधिक सरल
बनाने से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित
किया गया है। प्रस्तावित सुधारों से
उद्देश्य जीएसटी अनुपालन को कम

जटिल बनाना और कारोबारियों के लिए प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करना है। आईटीसी और रिफंड प्रक्रिया में सरलता पर जोर जीएसटी व्यवस्था में आईटीसी की उपलब्धता और रिफंड में होने वाली देरी कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। विशेष रूप से छोटे उद्यमों के लिए समय पर रिफंड मिलना कार्यशील पूंजी की उपलब्धता से जुड़ा है। ऐसे में परिपक्व की चर्चा में इन प्रक्रियाओं को अधिक सहज और पारदर्शी बनाने के उपायों को अहम माना जा रहा है। रिटर्न दाखिल करने और पंजीकरण से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने से कारोबारियों पर प्रशासनिक बोझ कम हो सकता है। तकनीक के बेहतर उपयोग के माध्यम से करदाताओं की समस्याओं का समयबद्ध समाधान और जीएसटी प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाए जाने की संभावना है। जीएसटी अधिकारियों की शक्तियों और अपराध संबंधी प्रावधानों पर चर्चा बैठक में जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी संबंधी

शक्तियों में संभावित बदलाव तथा कुछ जीएसटी अपराधों को गैर-आपराधिक श्रेणी में रखने के प्रस्तावों पर भी चर्चा का विषय बताया गया है। इसके साथ ही आपराधिक कारोबारों लागू होने की सीमा में बदलाव जैसे मुद्दे भी विचाराधीन हैं। इन प्रस्तावों का उद्देश्य कर अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ कारोबारियों को अनावश्यक कानूनी जटिलताओं से बचाने के बीच संतुलन स्थापित करना हो सकता है। हालाँकि, इन विषयों पर परिषद की अंतिम सहमति और सरकार के औपचारिक निर्णय के बाद ही किसी बदलाव की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। छोटे कारोबारियों और एमएसएमई की उम्मीदें छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी नियमों का पालन करना कई बार समय, संसाधन और अतिरिक्त लागत की चुनौती बन जाता है। यदि पंजीकरण, रिटर्न, आईटीसी और रिफंड की प्रक्रियाओं में व्यावहारिक सुधार होते हैं, तो इससे कारोबार संचालन में आसानी आ सकती है। फिलहाल

व्यापक जीएसटी दरों में बदलाव की प्रमुख अपेक्षा नहीं जताई जा रही है। ऐसे में बैठक का ध्यान कर दरों में व्यापक फेरबदल के बजाय प्रक्रियागत सुधारों और प्रशासनिक सरलता पर रहने की संभावना है। अंतिम फैसलों पर टिकी नजरें जीएसटी परिषद के प्रस्तावों और सिफारिशों का प्रभाव कारोबारियों, उद्योगों और करदाताओं पर पड़ सकता है। हालांकि, केवल चर्चा या प्रस्ताव के आधार पर किसी बदलाव को लागू नहीं माना जा सकता। अंतिम निर्णयों, अधिकारिक घोषणाओं और आवश्यक अधिसूचनाओं के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि जीएसटी व्यवस्था में कौन-कौन से सुधार प्रभावी होंगे। कारोबार जगत की निगाहें अब परिषद के अंतिम निर्णयों पर टिकी हैं। यदि प्रस्तावित प्रक्रियागत सुधार लागू होते हैं, तो जीएसटी अनुपालन को सरल बनाने और छोटे उद्यमों के लिए कारोबारी माहौल बेहतर करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर 2026 ।
हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की जेब पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
एअर इंडिया और एअर इंडिया
एक्सप्रेस ने घरेलू और
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए
फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का
फैसला किया है। एयरलाइंस
के अनुसार, बढ़ा हुआ सरचार्ज
9 अक्टूबर से लागू होगा। इससे
यात्रियों के हवाई टिकट की
कुल कीमत में वृद्धि हो सकती
है। वहीं, अकासा एयर ने भी
घरेलू उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज दोबारा
लागू करने का निर्णय लिया है। इसके
साथ ही एयरलाइन ने अंतरराष्ट्रीय
उड़ानों के लिए सरचार्ज में बढ़ोतरी की
है। इन फैसलों से हवाई यात्रा की
लागत और टिकटों की अंतिम कीमत
को लेकर यात्रियों की चिंता बढ़ सकती
है। ईंधन की लागत का असर किराये
पर विमानन क्षेत्र में ईंधन एक प्रमुख
परिचालन खर्च है। ईंधन की कीमतों में
उतार-चढ़ाव का असर एयरलाइंस
की लागत पर पड़ता है। ऐसी स्थिति

में कंपनियों अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए फ्यूल सरचार्ज जैसे उपाय अपनाती हैं। हालांकि, सरचार्ज में वृद्धि का वास्तविक असर यात्रियों पर कितना पड़ेगा, यह संबंधित उड़ान, यात्रा मार्ग



और लागू शुल्क पर निर्भर करेगा। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर असर एअर इंडिया समूह के फैंसले का असर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों श्रेणियों के यात्रियों पर पड़ सकता है। अकासा एयर की ओर से घरेलू उड़ानों पर सरचार्ज फिर से लागू करने और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए इसे बढ़ाने से यात्रियों को टिकट बुक करते समय कुल देय राशि पर विशेष ध्यान देना होगा। यात्रियों के लिए बेहतर होगा कि वे टिकट बुक करने से पहले एयरलाइन्स

की आधिकारिक वेबसाइट पर लाफ़, फ़्यूल सरचार्ज, अन्य शुल्क और टिकट की अंतिम कीमत की जांच कर लें। अलग-अलग मार्गों और टिकट श्रेणियों में शुल्क का प्रभाव अलग हो सकता है। फ़िलहाल, उपलब्ध जानकारी में सरचार्ज की अलग-अलग दरों और मार्गवार बढ़ोतरी का पूरा विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए यात्रियों के लिए वास्तविक अतिरिक्त खर्च का आकलन संबंधित एयरलाइन की ओर से जारी विस्तृत शुल्क सूची के आधार पर करना उचित होगा। फ़्यूल सरचार्ज की नई दरें एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, घरेलू उड़ानों पर कतरफा यात्रा के लिए दूरी के आधार पर 400 से 1,200 तक सरचार्ज लागू होगा। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में निर्धारित क्षेत्र के अनुसार 55 से 215 अमेरिकी डॉलर तक सरचार्ज रखा गया है। अकासा एयर की घरेलू उड़ानों पर दूरी के अनुसार 375 से 1,150 तक सरचार्ज लगेगा। भारत से कुवैत, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड और वियतनाम के लिए चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 2,500 का सरचार्ज निर्धारित किया गया है।

डॉक्टरों को महंगे उपहार देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नियामकीय व्यवस्था के लिए समिति बनेगी

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
संवाददाता अशोक कुमार सिंह
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर 2026 ।
फार्मास्युटिकल कंपनियाँ को भी ओर से
डॉक्टर्स को महंगे उपहार, प्रोत्साहन
और अन्य सुविधाएं देकर
प्रभावित करने की कथित
प्रथाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने
सख्त रुख अपनाया है।
अदालत ने केंद्र सरकार
को तीन सदस्यीय समिति
गठित करने का निर्देश
दिया है। समिति इन
गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए
वैधानिक व्यवस्था बनाने से जुड़े सुझाव
देगी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और
न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह
निर्देश उस याचिका पर सुनवाई के
दौरान दिया, जिसमें दवा कंपनियों
द्वारा डॉक्टरों को उपहार और अन्य
प्रोत्साहन देकर अपनी दवाओं के प्रचार
के लिए प्रभावित करने की आशंका पर
प्रभावी नियंत्रण की मांग की गई थी।
वैधानिक नियंत्रण के उपाय सुझाएगी
समिति अदालत के निर्देश के अनुसार,
प्रस्तावित समिति संबंधित पक्षों के सुझावों
और अभ्यावेदनों पर विचार करेगी।

इसके बाद वह अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य फार्मा कंपनियों की मार्केटिंग गतिविधियों के नियमन के लिए अधिक प्रभावी और बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था की संभावनाओं पर विचार करना है।

डॉक्टरों को महंगे उपहार देने वाली फार्मा कंपनियां पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

केंद्र को 3 सदस्यीय संविधि बनाने का निर्देश

कृषि मंत्रालय
आवास एवं शहरी विकास
स्वास्थ्य मंत्रालय
व्यापार एवं उद्योग

मामले में केंद्र सरकार को अनुपालन संबंधी हलचलनामा दाखिल करना होगा। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख निर्धारित की है। दवा प्रचार और चिकित्सा नैतिकता पर उठे सवाल याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियां डॉक्टरों को महंगे उपहार, यात्राओं और अन्य सुविधाओं के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास करती हैं, ताकि उनका ऐसी ऑफरों को अधिक प्राथमिकता मिले। ऐसी प्रथाओं को लेकर दवा कंपनियों की मार्केटिंग, चिकित्सकीय स्वतंत्रता और मरीजों के

हिताँ के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर सवाल उठते रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टरों के दवा संबंधी निर्णय मरीज की जरूरत, वैज्ञानिक प्रमाण और उपचार संबंधी मानकों पर आधारित होने चाहिए। यदि किसी प्रकार का आर्थिक लाभ या निजी प्रोत्साहन इन निर्णयों को प्रभावित करता है, तो इससे मरीजों के हिताँ और चिकित्सा नैतिकता पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका रहती है। अब नियामकीय व्यवस्था पर नजर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब समिति के गठन, उसके विचार-विमर्श और केंद्र सरकार के सौंपी जाने वाली सिफारिशों पर नजर रहेगी। हालांकि, समिति की सिफारिशें आने और सरकार द्वारा उन पर निर्णय लिए जाने के बाद ही नियामकीय व्यवस्था में संशोधित बदलावों की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। यह मामला केवल दवा कंपनियों की विपणन नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पारदर्शिता, चिकित्सकीय निर्णयों की निष्पक्षता और मरीजों के हिताँ से भी जुड़ा है। ऐसे में प्रभावी नियामन के साथ यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि दवाओं के चयन और उपचार संबंधी निर्णयों में मरीज का हित सर्वोपरि रहे।

हर जिले तक पहुंचा 5G, डिजिटल भारत में नई छलांग का दावा



भारतारथ खबर
Bhaaratatharath.com

संवाददाता अशोक कुमार सिंह
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर 2026 ।
भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार और दूरसंचार क्षेत्र में तकनीकी बदलावों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5G नेटवर्क देश के हर जिले तक पहुंच चुका है। उन्होंने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2026 के दसवें संस्करण का उद्घाटन करते हुए डिजिटल तकनीक को सुशासन, नागरिक सुविधाओं और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। प्रधानमंत्री के अनुसार, देश में 5.5 लाख से अधिक 5G बेस स्टेशन संचालित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2022 की तुलना में भारत में मोबाइल इंटरनेट की गति में लगभग दस गुना वृद्धि हुई है। इन आंकड़ों के माध्यम से उन्होंने दूरसंचार अवसंरचना के विस्तार और डिजिटल सेवाओं की बढ़ती भूमिका को सामने रखा। मोबाइल फोन बना सरकारी सेवाओं का अहम माध्यम प्रधानमंत्री ने कहा कि मोबाइल फोन का उपयोग अब केवल बातचीत

और संदेश भेजने तक सीमित नहीं रह गया है। यह सरकारी सेवाओं तक पहुंच, सुशासन, गेमिंग और डिजिटल सामग्री निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने डिजिटल तकनीक के नागरिकों को मिलने वाले लाभों का उल्लेख करते हुए कहा कि तकनीक का उद्देश्य लोगों की यात्रा, प्रतीक्षा और खर्च कम करना तथा सेवाओं को अधिक सुविधाजनक बनाना होना चाहिए। डिजिटल माध्यमों से सरकारी सेवाओं की उपलब्धता बढ़ने पर नागरिकों को कई काम घर बैठे करने की सुविधा मिल सकती है। हालांकि, डिजिटल सेवाओं का वास्तविक लाभ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि नेटवर्क की गुणवत्ता, इंटरनेट की वहीनीयता और डिजिटल साक्षरता किन्तनी व्यापक है तथा दूरदराज के क्षेत्रों में सेवाएं किन्तनी भरोसेमंद हैं। डिजिटल सुरक्षा और डीपफेक पर चिंता डिजिटल विस्तार के साथ बढ़ते साइबर जोखिमों की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने मोबाइल फोन और नेटवर्क की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने डीपफेक जैसी तकनीकी

यूनीतियों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर मजबूत ढांचा विकसित करने की आवश्यकता भी बताई। डीपफेक तकनीक के जरिए किसी व्यक्ति के चेहरे, आवाज या वीडियो में कृत्रिम बदलाव करके भ्रामक सामग्री तैयार की जा सकती है। ऐसी सामग्री का इस्तेमाल गलत सूचना फैलाने, लोगों को गुमराह करने और डिजिटल धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है। इसलिए तकनीकी विकास के साथ साइबर सुरक्षा, उपयोगकर्ताओं की जागरूकता और डिजिटल सामग्री की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। 5G से 6G तक की तकनीक पर मंथन इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक 'बैंगलूर' पंजी. वनज ठवनदकतपमें थीम के तहत किया जा रहा है। आयोजन में 100 से अधिक देशों की भागीदारी बताई गई है। सम्मेलन में 5G और 6G संचार तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह आयोजन दूरसंचार कंपनियों, तकनीकी

विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और नीति-निर्माताओं के लिए नई तकनीकों, निवेश की सभावनाओं तथा डिजिटल अवसरचना के भविष्य पर विचार-विमर्श का मंच है। डिजिटल भारत की अगली चुनौती देशभर में 5G कनेक्टिविटी का विस्तार डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। तेज नेटवर्क से ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमैडिसिन, डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नंस और कारोबार से जुड़ी सेवाओं को गति मिल सकती है। इसके बावजूद डिजिटल विकास की सफलता केवल बेस स्टेशनों की संख्या या इंटरनेट की गति से नहीं मापी जा सकती। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नेटवर्क की समान गुणवत्ता, सस्ती सेवाएं, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। भारत मोबाइल कांग्रेस 2026 में सामने रखे गए तकनीकी दृष्टिकोण के बीच अब चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि डिजिटल विस्तार का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और तकनीक आम नागरिक के जीवन को अधिक सुरक्षित, सरल तथा सुविधाजनक बनाए।

अंबानी के 1,600 सैटेलाइट प्लान से तेज हुई जियो-स्टारलिंग प्रतिस्पर्धा, मस्क ने उठाए सवाल

भारतार्थ खबर
Bhaarataraarth.com
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर 2026 ।
भारत में सेटेलाइट इंटरनेट सेवा को लेकर प्रतिस्पर्धा एक नए मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। रिलायंस जियो ने लगभग 1,600 लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) सेटेलाइट और 23 ग्राउंड स्टेशन विकसित करने की प्रस्तावित योजना पेश की है। इसका उद्देश्य उन दूरदराज गांवों, द्वीपों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुंचाना है, जहां मोबाइल टावर और फाइबर नेटवर्क स्थापित करना कठिन है। इसी बीच, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिनक को भारत में व्यावसायिक सेवा शुरू करने के लिए आवश्यक अंतिम मंजूरीयों का इंतजार है। इस घटनाक्रम ने भारत के सेटेलाइट इंटरनेट बाजार में प्रतिस्पर्धा और नियामकीय प्रक्रिया को लेकर बहस तेज कर दी है। क्या है जियो की 1,600 सेटेलाइट योजना? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में जियो ने अपनी प्रस्तावित सेटेलाइट कनेक्टिविटी योजना की जानकारी दी। इसके तहत पृथ्वी की निचली कक्षा में करीब 1,600 सेटेलाइट का नेटवर्क

विकसित करने और देशभर में 23 ग्राउंड स्टेशन स्थापित करने की योजना है। कंपनी ने इसे 'सॉवरन सेटैलाइट कनेक्टिविटी' की अवधारणा से जोड़ा है। ग्राउंड स्टेशन सेटैलाइट नेटवर्क और यरती पर मौजूद दूरसंचार ढांचे के बीच संपर्क स्थापित करने में मदद करेंगे। जियो की योजना अपने मौजूदा मोबाइल और फाइबर नेटवर्क के साथ सेटैलाइट कनेक्टिविटी को जोड़ने की है, ताकि पारंपरिक नेटवर्क की सीमाओं वाले क्षेत्रों में भी इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जा सके। कंपनी की प्रस्तुति में छह लाख से अधिक गांवों सहित भूमि और समुद्री क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य भी सामने आया है। स्टारलिक को लेकर मस्क ने क्यों उड़ा सवाल? स्टारलिक की मूल कंपनी स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क ने भारत में अपनी सेटैलाइट इंटरनेट सेवा को ऑर्बि कम्यूनिटी मिलने में हो रही देरी पर सार्वजनिक रूप से सवाल उड़ा हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली उद्योगपति स्टारलिक की भारत में एंटी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बाजार में अपना



दबदबा बनाए रखा जा सके। बाद की टिप्पणियों में उन्होंने मुकेश अंबानी का नाम लेकर भी सवाल किया। हालांकि, मस्क के आरोपों को स्थापित तथ्य के

रूप में नहीं देखा जा सकता। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि सैटेलाइट संचार सेवा प्रदाताओं के लिए नियामकीय प्रक्रिया निष्पक्ष और भेदभावरहित है तथा संबंधित कंपनियों की सुरक्षा संबंधी जांच जारी है। सरकार के अनुसार, आवश्यक मंजूरियाँ और सुरक्षा शर्तें पूरी करना सभी सेवा प्रदाताओं के लिए जरूरी है। जियो और स्टारलिक की तकनीक में क्या है अंतर? स्टारलिक पहले से बड़े बैथ्विक सैटेलाइट नेटवर्क के माध्यम से कई देशों में इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। इसके मुकाबले जियो की 1,600 सैटेलाइट योजना अभी प्रस्तावित नेटवर्क के चरण में है। दोनों कंपनियों का उद्देश्य उभ

क्षेत्रों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाना है, जहाँ पारंपरिक दूरसंचार ढांचे का विस्तार महंगा या मुश्किल है। सैटेलाइट इंटरनेट की मदद से पहाड़ी इलाकों, दूरदराज गांवों, द्वीपों, समुद्री क्षेत्रों और सीमावर्ती स्थानों में संपर्क बेहतर बनाने की संभावना है। आपदा के समय, परिवहन, उद्योग और अन्य विशेष सेवाओं में भी ऐसी तकनीक उपयोगी हो सकती है। हालांकि, वास्तविक सेवा की उपलब्धता नेटवर्क के विकास, स्पेक्ट्रम, सुरक्षा मंजूरी और अन्य नियामकीय आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी। क्या भारत में इंटरनेट की तत्परी बदलेगी? यदि जियो की योजना आगे बढ़ती है, तो भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के विकास बढ़ सकते हैं। इससे दूरदराज क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कारोबार तक पहुंच मजबूत करने की संभावना बनेगी। लेकिन उपभोक्ताओं को इसका वास्तविक लाभ कब और किस कीमत पर मिलेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। जियो की प्रस्तावित योजना और स्टारलिनिक की मंजूरी से जुड़ा विवाद केवल दो उद्योगपतियों को बीच प्रतिस्पर्धा का मामला नहीं है।

**180 यात्रियों की जान बचाने वाले पायलट स्मित मच्छार
को इज़रायल का सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान**

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर 2026।
जानलेवा हमले के बावजूद विमान
में सवार यात्रियों की सुरक्षा के लिए
अदम्य साहस और सुझबूझ दिखाने
वाले भारतीय मूल के पलाईडुबई के
कैप्टन स्मिथ मच्छार को इजरायल
के प्रतिष्ठित 'प्रेजिडेंशियल अवॉर्ड
फॉर सिविलियन हीरोइज्म' से
सम्मानित किया जाएगा। इजरायल
के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने उनकी
बहादुरी की सराहना करते हुए घोषणा
की कि स्वस्थ होने के बाद उन्हें
इजरायली जनता की ओर से यह
सम्मान प्रदान किया जाएगा।
कॉकपिट में हमले के बाद भी नहीं
खोया हौसला 30 सितंबर को दुबई
से तेल उड़ान जारी रही पलाईडुबई
की उड़ान FZ1073 में उस समय
गंभीर संकट पैदा हो गया, जब
सह-पायलट ने कथित तौर पर
कैप्टन स्मिथ मच्छार पर चाकू से
हमला कर दिया। घटना के दौरान

विमान तेजी से नीचे की ओर आया और उसमें सवार यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। गंभीर रूप से

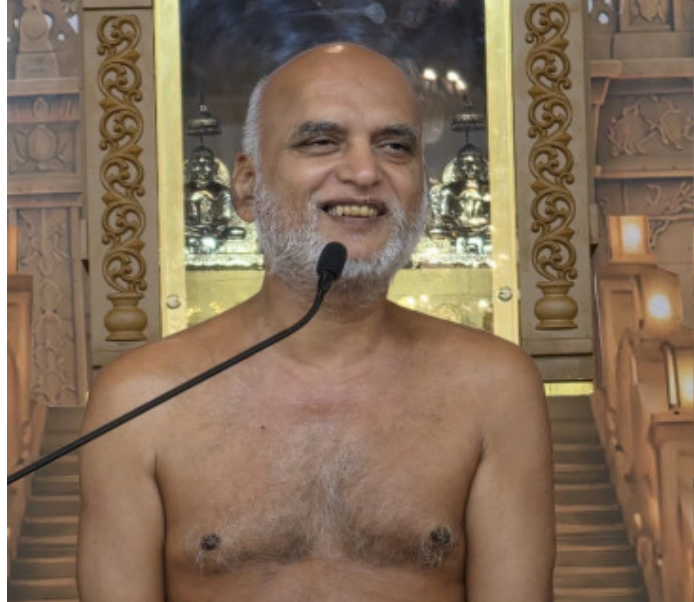
घायल होने के बावजूद मच्छार ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में सफलता हासिल की, जिससे यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को हस्तक्षेप करने तथा हमलावर को काबू करने में मदद मिली। इसके बाद दूसरे पायलटों ने विमान का नियंत्रण संभाला और सजुदी अरब के तबुक में उसकी सुरक्षित आपात लैंडिंग

कराई। इजरायली राष्ट्रपति ने की असाधारण बहादुरी की सराहना राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने कैप्टन मच्छार के साहस और पेशेवर दक्षता को बड़ी विमानन दुर्घटना टालने में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि मच्छार के स्वस्थ होने पर उन्हें इजरायल की जनता की ओर से नागरिक वीरता का राष्ट्रपति सम्मान प्रदान करना उनके लिए गौरव की बात होगी। यह सम्मान ऐसे समय में घोषित किया गया है, जब विमान में संकट के दौरान यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की भूमिका की भी व्यापक सराहना हो रही है। घटना में यात्रियों के साहसिक हस्तक्षेप और घायल पायलट की मदद से विमान को सुरक्षित उतारने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। बहादुरी के साथ पेशेवर जिम्मेदारी की मिसाल

कैप्टन मच्छार का यह साहसिक कदम विमानान क्षेत्र में संकट के समय धैर्य, प्रशिक्षण और जिम्मेदारी के महत्व को रेखांकित करता है। गंभीर खतरे के बीच उन्होंने जिस तरह मदद का रास्ता बनाया, उससे विमान में मौजूद लोगों को बचाने के प्रयासों को निर्णायक सहायता मिली। घटना ने विमानन सुरक्षा और कॉकपिट में चालक दल की सुरक्षा से जुड़े सवालों को भी सामने रखा है। संबंधित अधिकारियों की जांच से घटना के सभी पहलुओं पर स्पष्टता आने की उम्मीद है। कैप्टन मच्छार के लिए घोषित सम्मान केवल व्यक्तिगत बहादुरी की पहचान नहीं, बल्कि संकट के समय दूसरों की जान बचाने के लिए जोखिम उठाने वाले लोगों के साहस और मानवीय जिम्मेदारी का भी सम्मान है। उनके स्वरूप होने की कामना के साथ यह खबर उन सभी के लिए प्रेरणा है, जो कठिन परिस्थितियों में कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हैं।

हाह सुनिश्चित करना होगा कि सहायता का निर्धारण वास्तविक नुकसान और पात्रता के आधार पर हो, भुगतान समय पर किया जाए और पेयजल तथा पशु चारे जैसी तत्काल जरूरतों को प्राथमिकता मिले। साथ ही, जल संस्खारण, टिकाऊ कृषि और ग्रामीण रोजगार को दीर्घकालीन नीति का हिस्सा बनाना होगा। किसानों को राहत का भरोसा तभी मिलता है, जब सरकारी घोषणा उसके खेत, घर और पशुशाला तक वास्तविक सहायता के रूप में पहुँचती है। कृषि संकट के समय प्रशासन की सफलता केवल जमी की गई राशि या बनाई गई समितियों से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जानी चाहिए कि कितने प्रभावित परिवारों को समय पर सहारा मिला और वे अगली फसल के लिए कितनी मजबूती से तैयार हो सके। किसान की आर्थिक सुरक्षा केवल किसानों का मुद्दा नहीं, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता का आधार है। इसलिए राहत में देरी को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मानने के बजाय उसे कम करने की ठोस व्यवस्था बनानी होगी। सूखे से लड़ाई तभी सार्थक होगी, जब तात्कालिक सहायता के साथ भविष्य में ऐसे संकटों का सामना करने की क्षमता भी विकसित की जाए।

जिनदर्शन में समाए हैं जैन दर्शन के सात तत्त्व, आत्मकल्याण का मार्ग समझाया



भारतार्थ खबर
Bhaaraataarth.com
बेंगलूर, 9 अक्टूबर 2026।
निर्यापक अग्रणी मुनि जी 108 वीरसागर
जी महाराज ने दर्शन चार्तुमास 2026
के अंतर्गत आयोजित प्रवचन में
जिनदर्शन से सात तत्व कैसे नजर
आते हैं? विषय पर जैन दर्शन के
मूलभूत सिद्धांतों का आध्यात्मिक विवेचन
किया। उन्होंने जिनैन्द्र भगवान के दर्शन
को आत्मस्वरूप की पहचान, कर्मसिद्धांत
की समझ और मोक्षमार्ग पर चिंतन
करने की प्रेरणा से जोड़ते हुए सात
तत्वों के महत्त्व को रेखांकित किया।

प्रवचन में बताया गया कि जिनदर्शन का उद्देश्य केवल धार्मिक परंपरा का निर्वहण करना नहीं, बल्कि श्रद्धा के साथ आत्मनिरीक्षण करना और जीवन में संयम, विनम्रता तथा वीतरागता के आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त करना भी है। जैन दर्शन के सात तत्त्वकृजीव, अजीव, आस्रव, बंध, संयम, निर्जरा और मोक्ष आत्मा, कर्म और मुक्ति के पारस्परिक संबंध को समझने का आधार प्रस्तुत करते हैं। जीव और अजीव का अंतर समझने की प्रेरणा जैन दर्शन में जीव को चेतन द्रव्य और अजीव को अचेतन द्रव्य माना

माया है। जिनप्रतिमा के दर्शन के माध्यम से साधक शरीर और आत्मा के अंतर पर विचार कर सकता है। प्रतिमा का भौतिक स्वरूप अजीब है, जबकि जिन्हें भगवान के वीतराग गुण आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के आदर्श का स्मरण कराते हैं। इस दृष्टि से जिनदर्शन साधक को बाहरी गतिविधियों से आगे बढ़कर अपने भीतर की चेतना, विचारों और भावों का निरीक्षण करने की प्रेरणा देता है। प्रतिमा के सम्बन्ध आत्मा का भाव तभी अधिक सार्थक बनता है, जब वह आत्मचिंतन और आचरण में सुधार का माध्यम बनता है। आसन्न और बंध से सम्बन्धित सिद्धांत जैन कर्मसिद्धि के अनुसार आसन्न कर्मों के प्रवाह और बंध आत्मा के साथ कर्मों के बंधने की प्रक्रिया को दर्शाता है। राग-द्वेष, क्रोध, मान, माया और लोभ जैसे कषाय व्यक्ति के भावों तथा व्यवहार को प्रभावित करते हैं। प्रवचन के विषयगत संदेश के अनुसार, जिनदर्शन के समय साधक को अपने भीतर के भावों पर भी ध्यान देना चाहिए। उसे विचार करना चाहिए उसके व्यवहार में अहंकार, छल, ईर्ष्या और आसक्ति का कितना प्रभाव है तथा वह दूसरों के प्रति कितनी करुणा, क्षमा और विमर्शता रखता है। इस प्रकार जिनदर्शन आत्मनिरीक्षण के अवसर बन सकता है। केवल मंदिर में उपस्थित होना कर्मबंधन से स्वतः मुक्ति की गारंटी नहीं है, इसके लिए

सम्यक् दृष्टि, संयम और भावों की शुद्धता के प्रति निरंतर प्रयास आवश्यक है। संवर और निर्जरा से आत्मशुद्धि का संदेश जैन दर्शन में संवर का अर्थ नए कर्मों के आगमन को रोकना और निर्जरा का अर्थ आत्मा से बंधे कर्मों का क्षय होना है। संयम, तप, त्याग, सावधानी और कषायों पर नियंत्रण को इस दिशा में महत्त्वपूर्ण माना गया है। जिनेंद्र भगवान् की शांत और वीतराग मुद्रा साधक को अपने मन को स्थिर करने तथा राग-द्वेष से दूर रहने की प्रेरणा देती है। दर्शन के दौरान जिनेंद्र भगवान् के गुणों का स्मरण करते हुए व्यक्ति अपने विचारों और व्यवहार की समीक्षा कर सकता है। वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति बाहरी क्रियाओं के साथ आंतरिक परिवर्तन और संयमपूर्ण आचरण से जुड़ी है। मोक्ष है आत्मा की परम शुद्ध अवस्था जैन दर्शन का सातवाँ तत्त्व मोक्ष है। इसे आत्मा की वह परम अवस्था माना गया है, जिसमें समस्त कर्मों का पूर्ण क्षय हो जाता है और आत्मा कर्मबंधन से मुक्त हो जाती है। जिनेंद्र भगवान् का वीतराग स्वरूप इसी आध्यात्मिक आदर्श का स्मरण कराता है। प्रवचन में प्रतिपादित विचारों के अनुसार, जिनदर्शन को आत्मविवेक से जोड़ने पर साधक अपने जीवन के उद्देश्य और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा पर

भीरीतर से विचार कर सकता है। जिनेंद्र भगवान् के गुणों का स्मरण केवल प्रशंसा तक सीमित न रहे, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर अपने आचरण में विनम्रता, क्षमा और संयम विकसित करने का प्रयास भी किया जाए। दैनिक जीवन में जिनदर्शन की सार्थकता गृहस्थ जीवन में परिवार, व्यवसाय और सामाजिक दायित्वों के बीच व्यक्त अनेक चुनौतियों का सामना करता है। ऐसे में धार्मिक साधना उसे अपने विचारों और व्यवहार का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करती है। यदि जिनदर्शन के बाद व्यक्त क्रोध पर नियंत्रण रखने, दूसरों के प्रति क्षमाभाव विकसित करने और लोभ-अहंकार को कम करने का प्रयास करता है, तो धार्मिक चिंतन उससे दैनिक जीवन में भी अभिव्यक्त होने लगता है। दर्पण चतुर्मास 2026 के अंतर्गत प्रस्तुत इस आध्यात्मिक विषय का केंद्रीय संदेश यही रहा कि जैन दर्शन के सात तत्त्वों को समझना आत्मस्वरूप, कर्मसिद्धांत और मोक्षमार्ग की दिशा में चिंतन को गहरा कर सकता है। जिनेंद्र भगवान् के वीतराग स्वरूप से प्रेरणा लेकर साधक आत्मनिरीक्षण, संयम और आत्मकल्याण की ओर अग्रसर होने का संकल्प ले सकता है। समाचार प्रेषक विपिन कुमार जैन, बेंगलुरु।

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
बेंगलुरु, 9 अक्टूबर 2026।
राजस्थान के भीनमाल क्षेत्र स्थित
लुणावास 52 वीर धाम के भोपाजी
वागाराम के बेंगलुरु आगमन पर
समाजबंधुओं एवं श्रद्धालुओं ने

सुख-समृद्धि, खुशहाली एवं मंगलकामना की। धार्मिक आस्था और पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में समाज की सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान और आपसी जुड़ाव की भावना दिखाई दी। धार्मिक आस्था और

इस अवसर पर भोपाजी वागाराम ने उपस्थित श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया और धर्म, सदाचार तथा समाजसेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम में श्रद्धा और उत्साह का वातावरण रहा। समाजजनों ने धार्मिक एवं सांस्कृ



आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में समाजजन और श्रद्धालु उपस्थित रहे। पुष्पमालाओं और पारंपरिक साफे से उनका अभिनंदन किया गया तथा उपस्थित लोगों ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। समारोह के दौरान श्रद्धालुओं ने क्षेत्र, समाज और परिवारों की

सामाजिक एकता का संदेश स्वागत समारोह में समाजबन्धुओं ने धार्मिक परंपराओं के संरक्षण, सामाजिक एकता को मजबूत करने और भावी पीढ़ियों तक सांस्कृतिक मूल्यों को प्रवर्धन पर जोर दिया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने भोपाजी वागाराज के बँगलुरु आगमन को समाज के लिए हर्ष और सौभाग्य का अवसर बताया।

तिक परंपराओं से जुड़े आयोजनों को सामाजिक सदभाव और एकजुटता का माध्यम बताया। समारोह के माध्यम से समाजबंधुओं ने अपनी धार्मिक आस्था के साथ-साथ पारस्परिक सहयोग और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की भावना भी व्यक्त की। समाचार प्रेषक दलपतसिंह भायल, बेंगलुरु।

जयनगर में स्मार्ट पाकिंग का तैयारी, घरों के सामने वाहन खड़ा करने पर स्थानीय निवासियों से नहीं लगेगा शुल्क

भारतार्थ खबर
Bhaarataraarth.com
बेंगलुरु, 9 अक्टूबर 2026।
बेंगलुरु के जयनगर क्षेत्र में यातायात
जाम की समस्या कम करने और
जाएगा, जिससे पार्किंग स्थलों की
निगरानी और वाहनों के आवागमन
को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा
सके। व्यापारियों ने शुरू में राहत
की मांग उठाई जयनगर में स्मार्ट



वाहन चालकों को व्यवस्थित पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था जल्द लागू की जाएगी। बंगलुरु साउथ सिटी कॉर्पोरेशन के आयुक्त के. एन. रमेश ने स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था के तहत स्थानीय निवासियों से उनके घरों के सामने वाहन खड़ा करने पर पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। कॉर्पोरेशन का उद्देश्य जयनगर की चुनिंदा व्यावसायिक सड़कों पर पार्किंग को व्यवस्थित करना, यातायात का दबाव कम करना और वाहन चालकों के लिए पार्किंग की उपलब्धता आसान बनाना है। प्रस्तावित व्यवस्था में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया

पार्किंग पहले को लागू करने की तैयारी के बीच जयनगर ट्रैडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कॉर्पोरेशन आयुक्त के सम्मक्ष अपनी मांगें रखीं। व्यापारियों ने पार्किंग शुल्क कम करने और शुरुआती 30 मिनट तक नि:शुल्क पार्किंग की सुविधा देने का आग्रह किया। आयुक्त के. एन. रमेश ने कहा कि व्यापारियों की मांगों पर व्यावहारिक लाभ और संभावित कठिनाइयों का आकलन करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इससे स्पष्ट है कि पार्किंग शुल्क से संबंधित मांगों पर अंतिम निर्णय चुनित के बाद लिया जाएगा। अगलदा व्यावसायिक सड़कों पर ही लोगों

पार्किंग पहले को लागू करने की तैयारी के बीच जयनगर ट्रैडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को रॉकीशॉन आयुक्त के सम्मक्ष अपनी मांगें रखीं। व्यापारियों ने पार्किंग शुल्क कम करने और शुरुआती 30 मिनट तक नि:शुल्क पार्किंग की सुविधा देने का आग्रह किया। आयुक्त के. एन. रमेश ने कहा कि व्यापारियों की मांगों पर व्यावहारिक लाभ और संभावित कठिनाइयों का आकलन करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इससे स्पष्ट है कि पार्किंग शुल्क से संबंधित मांगों पर अंतिम निर्णय आयुक्त के बाद लिया जाएगा। चुनिंदा व्यावसायिक सड़कों पर ही लगेगा

शुल्क आयुक्त ने स्पष्ट किया कि स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था जयनगर की चुनिंदा व्यावसायिक सड़कों पर लागू होगी। स्थानीय निवासियों को उनके घरों के सामने वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग शुल्क नहीं देना होगा वहीं, निर्धारित व्यावसायिक सड़कों पर सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक पार्किंग शुल्क लागू रहेगा। कोर्पोरेशन के थालारियों और खरीदारों से इस पहल में सहयोग करने की अपील की है। प्रशासन के अनुसार, व्यवस्थित पार्किंग से सड़कों पर वाहनों में मदद मिल सकती है। सीसीटीवी और मोबाइल ऐप से होगी पार्किंग की निगरानी प्रस्तावित स्मार्ट पार्किंग प्रणाली में चुनिंदा सड़कों पर सीसीटीवी निगरानी, मोबाइल ऐप के माध्यम से वास्तविक समय में पार्किंग की जानकारी और निर्देश देने वाले सूचना-पट्ट लगाए जाएंगे। पार्क एंड एंजेंसी के प्रतिनिधियों के अनुसार, लंबे सुविधाओं से वाहन चालकों को उपलब्ध पार्किंग स्थलों की जानकारी मिल सकेगी। इससे पार्किंग की तलाश में अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमने की जरूरत कम होने और अनावधिक पार्किंग पर नियंत्रण में सहायता मिलने की उम्मीद है।

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com

विजयपुरा, 9 अक्टूबर 2026।
कर्नाटक में सूखे की स्थिति, किसानों की आर्थिक बहाली, कृषि ऋण माफी और डेयरी प्रोत्साहन राशि के युगतान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी. वाई. विजयेंद्र ने किसानों को प्रति हेक्टेयर 50 हजार मुआवजा देने, 5 लाख तक के कृषि ऋण माफ करने और दूध उत्पादकों का बकाया प्रोत्साहन जारी करने की मांग की। उन्होंने नारायणपुर जलाशय से तेलंगना के लिए पानी छोड़ने के कथित निर्णय भी सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। विजयपुरा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं की समस्याओं को समाधान में विफल रही है। उन्होंने कहा कि सूखे के कारण कृषि क्षेत्र पर दबाव बढ़ रहा है, जबकि किसानों को अपेक्षित राहत नहीं मिल रही। राज्य सरकार ने इन आरोपों पर इस वक्तव्य में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सेवा संकल्प अभियान के तहत सफाईकर्मियों का सम्मान विजयेंद्र ने बताया कि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशभर में 'सेवा संकल्प अभियान' आयोजित किया है। कर्नाटक में भी इस अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। विजयपुरा में आयोजित



कार्यक्रम के दौरान सफाईकर्मियों को योगदान दिया गया और उनके सम्मान के साथ किया गया। विजयद्वे प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि अभियान का उद्देश्य सेवा, विकास और जनभागीदारी के संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। किसानों को मुआवजा और कृषि ऋण माफी की मांग भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सूखे से प्रभावित किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने प्रति हेक्टेयर 50 हजार मुआवजा, 5

लाख तक के कृषि ऋण की माफी और कृषि कार्यों के लिए प्रतिदिन आठ घंटे तीन-फेज बिजली उपलब्ध कराने की मांग दोहराई। उन्होंने बताया कि किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा ने लिंगासुगुर से बेल्लारी तक 'बेल्लारी चलो' पदयात्रा भी

निकाली थी। विजयेंद्र के अनुसार, विधानसभा के विशेष सत्र में भी किसानों की प्रेरानियों का मुद्दा उठाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से घोषित 2,500 की राहत किसानों की जरूरतों के मुकाबले और इसके वितरण में भी नाममन आई है। विजयेंद्र डी.के. शिक्कुमार की हो गेने संबंधी टिप्पणियों ने ठोस कहा कि किसानों को समझने और उनका ने के लिए जमीनी स्तर पर जांचवाई जरूरी है। महाराष्ट्र कर्ज माफी और डेयरी करने की मांग विजयेंद्र महाराष्ट्र में किसानों के उ रहे राहत उपायों का त्रु हण कर्नाटक में भी

कृषि ऋण माफी लागू करने की मांग की। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा के कार्यकाल में घोषित डेयरी प्रोत्साहन राशि का वकाला जारी करने की अपील की। उन्होंने मांग की कि सूखे की स्थिति समाप्त होने तक दूध उत्पादकों को कम से कम पाँच महीने के लिए प्रति लीटर 5 क.प. अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाए। उनका कहना था कि फसल खराब होने, कर्ज के बढ़ते बोझ और पानी की कमी से किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। ऐसे समय में सरकार को किसानों का भरोसा बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। नारायणपुर जलाशय से तेलंगाना को पानी देने पर सवाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि नारायणपुर जलाशय से तेलंगाना के लिए लगभग दो टीएमसी पानी छोड़ने की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि जब कर्नाटक के कई क्षेत्रों में किसान और आम नागरिक पानी की कमी का सामना कर रहे हैं, तब इस तरह के निर्णय के आधार और आवश्यकता के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से पूछा कि पानी छोड़ने का निर्णय किसने लिया और इसका पीछे क्या परिस्थितियाँ थीं। विजयेंद्र ने मांग की

के राज्य सरकार कर्नाटक के किसानों और पेयजल जरूरतों पर पड़ने वाले असरों संभावित प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। हालांकि, पानी छोड़े जाने की मात्रा निर्णय की आधिकारिक स्थिति और संबंधित जल-बंटवारा व्यवस्था के बारे में स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस मुद्दे पर अंतिम निष्कर्ष से पहले सरकार और संबंधित विभागों का आधिकारिक पक्ष महत्वपूर्ण होगा।

फॉर्म-7 आवेदन पर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई का विरोध मतदाता सूची से जुड़े फॉर्म-7 आवेदन के मुद्दों पर विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन जमा करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को प्राथमिकी दर्ज करने की धमकी देकर डराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया के तहत आवेदन देने के अधिकार को राजनीतिक आधार पर अपराध नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने संबंधित मामले में न्यायालय के आदेश का भी उल्लेख किया और मांग की कि भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर कार्रवाई नहीं की जाए।

विजयेंद्र ने कहा कि पार्टी ऐसी कथित धमकियाँ के आगे नहीं झुकेगी और जनमत से जुड़े मुद्दों पर अपना विरोध जारी रखेगी।

जलाहल्लों क्रॉस अंडरपास का काम जल्द शुरू करने के निर्देश, गड्डों की मरम्मत में भी तेजी

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
बेंगलुरु, 9 अक्टूबर 2026।
बेंगलुरु में यातायात जाम से राहत दिलाने और सड़कों की स्थिति सुधारने के उद्देश्य से मुख्य आयुक्त महेश्वर राव ने जलाहल्ली क्रॉस अंडरपास का निर्माण कार्य जल्द शुरु करने तथा कांतीरवा स्टूडियो रोड पर गड्ढों की तत्काल मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बेंगलुरु पश्चिम नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न स्थानों का दौरा कर विकास कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया और अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने को कहा। जलाहल्ली क्रॉस पर अंडरपास निर्माण की तैयारी जलाहल्ली क्रॉस पर यातायात जाम की समस्या कम करने के लिए प्रस्तावित अंडरपास के निर्माण में कुल 48 संपत्तियों का अधिग्रहण किया जाना है। इनमें से 22 संपत्तियों का अधिग्रहण कर उन्होंने नगर निगम के कब्जे में लिया जा चुका है, जबकि शेष 26 संपत्तियों का अधिग्रहण अभी बाकी है। मुख्य आयुक्त ने अधिकारियों को शेष संपत्तियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध हो चुकी है, वहां पहले सर्विस रोड तैयार की जाए और उस पर वाहनों की आवाजाही शुरू की जाए। इसके



बाद अंडरपास का निर्माण कार्य जल्द शुरु करने की दिशा में कार्रवाई की जाए। 2.5 किलोमीटर सड़क पर क्लाइंट टॉपिंग का काम तेज करने के निर्देश मुख्य आयुक्त ने एनटीटीएफ से सोनल गारमेट होटेल्स एंटीबीएस क्रॉस जंक्शन तक लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क पर चल रहे क्लाइंट टॉपिंग कार्य की भी समीक्षा की। इस मार्ग पर जल बोर्ड की ओर से पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है, जिसके कारण सड़क निर्माण कार्य की गति प्रभावित हो रही है। उन्होंने अधिकारियों को पाइपलाइन का काम जल्द पूरा

पर निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध हो चुकी है, वहां पहले सर्विस रोड तैयार की जाए और उस पर वाहनों की आवाजाही शुरू की जाए। इसके



बाद अंडरपास का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने की दिशा में कार्रवाई की जाए। 2.5 किलोमीटर सड़क पर हाइड्रो टॉपिंग का काम तेज करने के निर्देश मुख्य आयुक्त ने एनटीटीएफ से सोनल गार्मेट होते हुए टीवीएस क्रॉस जंक्शन तक लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क पर चल रहे हाइड्रो टॉपिंग कार्य की भी समीक्षा की। इस मार्ग पर जल बोर्ड की ओर से पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है, जिसके कारण सड़क निर्माण कार्य की गति प्रभावित हो रही है। उन्होंने अधिकारियों को पाइपलाइन का काम जल्द पूरा

कराने और निर्माण कार्य के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। पाइपलाइन का काम पूरा होने के बाद सड़क के एक हिस्से पर

की जाए। सड़क किनारे कबरे का अनुचित निस्तारण न केवल शहर की स्वच्छता को प्रभावित करता है, बल्कि सार्वजनिक स्थानों के रखरखाव और नागरिक सुविधाओं के लिए भी चुनौती बनता है। ऐसे में नियमित निगरानी और प्रभावों का रैकार्ड बनाना पर जोर दिया गया। कांतीरवा स्टूडियो रोड के गड्ढे तत्काल भरने को कहा निरीक्षण के दौरान मुख्य आयुक्त ने कांतीरवा स्टूडियो रोड पर बने गड्ढों की स्थिति का जायजा लिया और उनकी तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए। अधिकारियों के अनुसार, सड़क के एक हिस्से में गड्ढे भरने का काम पहले से चल रहा है। इजीनियरों ने बताया कि यह शेष हिस्से में बारिश नहीं होती है, तो वहां भी उसी रात गड्ढों की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। सड़क की स्थिति सुधारने के लिए मौसम के अनुकूल परिस्थितियों में काम तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया। निरीक्षण के दौरान बेंगलुरु पश्चिम नगर निगम के आयुक्त डॉ. राजेंद्र के.वी., मुख्य अभियंता स्वयंप्रभा, सजीव राजू सहित कार्यपालक अभियंता, सहायक कार्यपालक अभियंता और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com

बैंगलुरु, 9 अक्टूबर 2026। बैंगलुरु उत्तर नगर निगम में नागरिकों की शिकायतों के लिए और प्रगामी समाधान के लिए 'सहाय 2.0' सॉफ्टवेयर के माध्यम से निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। निगम आयुक्त पोम्माला सुनील कुमार के नेतृत्व में शिकायतों को दर्ज करने, संबधित विभागों तक पहुंचाने और संबंधित निस्साधन की प्रगति पर नजर रखने की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। शुक्रवार को आयोजित आयुक्त के 55वें फोन-इन कार्यक्रम में नागरिकों से 41 कॉल प्राप्त हुईं, जिनके माध्यम से कुल 48 शिकायतों सामने आईं। अधिकारियों को लंबित मामलों की समीक्षा कर निर्धारित समयसीमा में समाधान सुनिश्चित करके के निर्देश दिए गए। सड़क और सफाई से जुड़ी शिकायतें सबसे अधिक फोन-इन कार्यक्रम में प्राप्त 48 शिकायतों में सबसे अधिक 22 शिकायतें सड़क रखरखाव और इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित थीं। इनमें छह गड्डों, चार सड़क किनारे की नालियों, फुटपाथ और फुटपाथ पर अतिक्रमण से जुड़ी तीन-तीन शिकायतें शामिल थीं। इसके अलावा निर्माण मलबा हटाने की दो, अनधिकृत निर्माण की दो, सड़क कटिंग

की एक और जलभराव की एक शिकायत प्राप्त हुई। अन्य विभागों से प्राप्त शिकायतों में ठोस कचरा प्रबंधन विभाग की सात, विद्युत विभाग की



चार, वन विभाग की चार, स्वास्थ्य विभाग की चार, पशु चिकित्सा विभाग की तीन, ई-खाता एवं खाता सेवाओं की दो तथा चुनाव शाख और यातायात इंजीनियरिंग प्रकोष्ठ की एक-एक शिकायत शामिल थी। अब तक 3,319 शिकायतें, 260 लंबित आयुक्त के फोन-इन कार्यक्रमों के माध्यम से अब तक कुल 3,319 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 260 शिकायतें अभी लंबित बताई गई हैं। निगम के अनुसार, इन शिकायतों को 'सहाय 2.0' प्रणाली में दर्ज कर संबंधित अधिकारियों को सौंपा जाता है और उनके निस्तारण की स्थिति की लगातार समीक्षा की जाती है। फोन-इन कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे निगम प्रशासन के सामने रखने का अवसर देना और शिकायतों के

समाधान की प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह बनाना है। दो लाख से अधिक शिकायतें दर्ज, 1,99,705 का निस्तारण निगम की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) के गठन से पहले, 1 जनवरी 2023 से 31 अगस्त 2025 के बीच कुल 1,17,175 शिकायतें दर्ज हुई थीं। इनमें से 2,193 शिकायतें लंबित थीं। जीबीए अविधि में 1 सितंबर 2025 से 9 अक्टूबर 2026 तक 83,653 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 1,123 लंबित बताई गईं। दोनों अवधियों को मिलाकर कुल 2,00,828 शिकायतें दर्ज की गईं और 1,99,705 का निस्तारण किया गया। निगम के आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में 1,123 शिकायतें लंबित थीं। शुक्रवार के फोन-इन कार्यक्रम में प्राप्त 48 नई शिकायतों को जोड़ने के बाद लंबित शिकायतों की कुल संख्या 1,171 हो गई। सड़क रखरखाव से जुड़ी 540 शिकायतें लंबित 9 अक्टूबर 2026 तक बेंगलुरु उत्तर नगर निगम के विभिन्न विभागों में लंबित 1,123 शिकायतों में सबसे अधिक 540 सड़क रखरखाव एवं इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित हैं। इसके बाद टोस कचरा

प्रबंधन विभाग की 279 और विद्युत विभाग की 93 शिकायतें लंबित हैं। इस प्रकार हैं विज्ञापन विभाग 6, विभागवार लंबित शिकायतों का विवरण—
बीबीएमपी चुनाव शाखा 2, ई—खाता एवं खाता सेवाएं 30, शिक्षा विभाग कृ कृ 37, स्वास्थ्य विभाग 16, ऑप्टिकल फाइबर केबल 2, पार्क एवं खेल मैदान 3, परियोजना केंद्रीय प्रभाग 22, संपत्ति कर सेवाएं 1, राजस्व विभाग कृ 3, सड़क रखरखाव एवं इंजीनियरिंग 54, स्वच्छता विभाग 14, टोस करारा प्रबंधन 279, नगर नियोजन विभाग 17, यातायात इंजीनियरिंग प्रकोष्ठ 34, पशु चिकित्सा विभाग 22 निगम के अनुसार, लंबित शिकायतों में से 21 पर काम जारी है, 17 दीर्घकालिक समाधान से संबंधित हैं, 930 पंजीकृत स्थिति में हैं और 151 शिकायतें दोबारा खोली गई हैं। इन श्रेणियों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कई माध्यमों से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा नागरिक निगम कार्यालय, ईमेल, समाचार पत्रों, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे विभिन्न माध्यमों से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।

बेंगलुरु, शनिवार , 10 अक्टूबर 2026

प्रादेशिक समाचार

Bhaarataarth.com

4

तुलु भाषा को संवैधानिक पहचान दिलाने की मुहिम तेज, पूरे कर्नाटक में मान्यता की तुलु भाषा को संवैधानिक पहचान दिलाने की मुहिम तेज, पूरे कर्नाटक में मान्यता की मांग मांग

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
मंगलुरु, 9 अक्टूबर 2026।
तटीय कर्नाटक की भाषाई विरासत और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी तुलु भाषा को व्यापक मान्यता दिलाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। कर्नाटक सरकार द्वारा दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में



तुलु को अतिरिक्त आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के फैसले का स्वागत करते हुए भाषा समर्थकों ने अब इसे पूरे राज्य में लागू करने तथा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग उठाई है। 8 अक्टूबर को मंगलुरु में भाषा समर्थकों ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि चुनिंदा जिलों तक सीमित आधिकारिक मान्यता

के अनुसार, राज्य सरकार का हालिया निर्णय लंबे समय से चल रहे भाषा आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन उनकी प्रमुख मांग अभी पूरी नहीं हुई है। तुलु को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने से भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक मान्यता मिलेगी और उसके साहित्य, शिक्षा, शोध तथा संरक्षण को बढ़ावा देने

के नए अवसर खुल सकते हैं। कुडला इकाई की अध्यक्ष राजश्री चंद्रशेखर ने कहा कि तुलु को अतिरिक्त आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलना महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन अंतिम लक्ष्य संवैधानिक मान्यता प्राप्त करना है। संगठन ने राज्य सरकार से इस दिशा में केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से पक्ष रखने का आग्रह

किया है। तुलु विकास प्राधिकरण और भाषा भवनों की मांग भाषा समर्थकों ने तुलु के संरक्षण और संवर्धन के लिए अलग तुलु विकास प्राधिकरण गठित करने तथा उडुपी और पुनूर में तुलु भवन स्थापित करने की मांग भी रखी है। प्रस्तावित भवनों को भाषा के अध्ययन, शोध, दस्तावेजीकरण और सांस्कृतिक गतिविधियों के स्थायी केंद्र के रूप

में विकसित करने की बात कही गई है। संगठन ने प्रशासनिक कार्यों में तुलु के प्रभावी उपयोग के लिए प्रारंभिक चरण में कम से कम पांच करोड़ रुपये का विशेष अनुदान देने की मांग की है। इसके तहत अनुवाद व्यवस्था, सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और डिजिटल सुविधाओं के विकास पर ध्यान देने का सुझाव दिया गया है। तुलु लिपि को सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से प्रोत्साहित करने की मांग भी उठाई गई है। इसके अतिरिक्त, समर्थक चाहते हैं कि तुलु को पड़ोसी राज्य केरल में भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास किए जाएं। समृद्ध भाषाई विरासत को संरक्षण देने की पहल तुलु दक्षिण भारत की प्रमुख द्रविड़ भाषाओं में से एक है। इसका व्यापक सांस्कृतिक संबंध तटीय कर्नाटक के तुलुनाडु क्षेत्र से है। लोक परंपराओं, धार्मिक अनुष्ठानों, यक्षगान और मौखिक साहित्य में तुलु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भाषा समर्थकों का मानना ​​है कि प्रशासनिक मान्यता से नई पीढ़ी में भाषा के प्रति रुचि बढ़ेगी तथा इसके साहित्य और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण को संस्थागत भवनों को भाषा के अध्ययन, शोध, आधार मिलेगा। हालांकि, भाषा की सांस्कृतिक महत्ता और राज्य स्तर पर मिली अतिरिक्त आधिकारिक

मान्यता को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने से अलग समझना आवश्यक है। राज्य में प्रशासनिक उपयोग की अनुमति और संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दो अलग प्रक्रियाएं हैं। आठवीं अनुसूची में शामिल करने का फैसला केंद्र के स्तर पर भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। तुलु को इस सूची में शामिल करने की मांग लंबे समय से उठती रही है। केंद्र सरकार ने संसद में पहले भी स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त भाषाओं को अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई अंतिम, वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित नहीं है और इस विषय पर संबंधित मांगों पर विचार किया जाता है। ऐसे में तुलु भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए राज्य सरकार की पहल, केंद्र के स्तर पर विचार और आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। भाषा समर्थकों की ताजा मांग ने इस विषय को फिर चर्चा में ला दिया है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार पूरे कर्नाटक में तुलु प्रशासनिक उपयोग के विस्तार, प्रस्तावित विकास प्राधिकरण, भाषा भवनों और विशेष अनुदान की मांगों पर क्या कदम उठाती है। साथ ही, आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर केंद्र के समक्ष आगे क्या पहल की जाती है।

प्रधानमंत्री पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा युवा मोर्चा की शिकायत, एफआईआर दर्ज करने की मांग

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
बेंगलुरु, 9 अक्टूबर 2026।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)

इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों और बयानों से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायतकर्ताओं ने विशेष रूप से अभिजीत दीपक द्वारा प्रधानमंत्री को कथित तौर पर 'वोट चोर' कहे जाने पर आपत्ति जताई।



युवा मोर्चा ने अभिजीत दीपक और ध्रुव राठी के विरुद्ध प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने की मांग की है। इस संबंध में युवा मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बेंगलुरु के उम्परपेट पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दी और मामले की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया। भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं का आरोप है कि प्रधानमंत्री के लिए

बावजूद भाषा की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने संबंधित व्यक्तियों के बयानों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का आग्रह किया। युवा मोर्चा के नेताओं ने यह भी कहा कि यदि शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन विशेष प्रदर्शन करेगा। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में पुलिस की ओर से शिकायत पर की गई कार्रवाई अथवा एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि नहीं है। मतदाता सूची और एसआईआर प्रक्रिया का भी उदाहरण मुद्रा शिकायत के दौरान युवा मोर्चा के नेताओं ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया पहले भी अपनाई गई है और इसके इतिहास पर राजनीतिक बहस करते समय तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेताओं ने विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। यह मांग भाजपा युवा मोर्चा के प्रतिनिधियों का राजनीतिक पक्ष है; संबंधित आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है। युवा मोर्चा के पदाधिकारी रहे मौजूद उम्परपेट पुलिस थाने में शिकायत देने वाले प्रतिनिधिमंडल में भाजपा युवा मोर्चा के बेंगलुरु उत्तर जिला अध्यक्ष यतिन वेंकटेश, बेंगलुरु मध्य जिला अध्यक्ष जगदीश आर. चंद्रा, बेंगलुरु दक्षिण जिला अध्यक्ष प्रमोद श्रीनिवास और युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव दीपक कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। फिलहाल, मामले में पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया और शिकायत पर आगे की कार्रवाई का विवरण सामने आना बाकी है। शिकायत में लगाए गए आरोपों और संबंधित व्यक्तियों का पक्ष सामने आने के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

कच्छ के ऊर्जा पार्क में भीषण सड़क हादसा, सात श्रमिकों की मौत 20 से अधिक घायल

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
भुज, 9 अक्टूबर 2026। गुजरात के कच्छ जिले में खारड़ स्थित विशाल नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के भीतर शुक्रवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में सात श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। श्रमिकों को लेकर जा रहे बोलरो कैंपर और एक ट्रक की आमने-सामने टक्कर के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया तथा घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। हादसे के कारणों और संभावित लापरवाही की जांच की जा रही है। तड़के तीन से चार बजे के बीच हुई टक्कर पुलिस के अनुसार, दुर्घटना शुक्रवार सुबह करीब तीन से चार बजे के बीच खारड़ के पास स्थित नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के अंदर हुई। विपरीत दिशाओं से आ रहे ट्रक और श्रमिकों से भरे बोलरो कैंपर की

जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कैंपर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार कई श्रमिक अंदर फंस गए। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे। क्षतिग्रस्त वाहन में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। बचाव दल ने सात श्रमिकों को बाहर निकाला, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों का उपचार, मृतकों के शव भुज भेजे गए प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे में 20 से अधिक श्रमिक घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए



अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ घायलों की स्थिति के बारे में तत्काल विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी थी। पुलिस के मुताबिक, मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए खारड़ से भुज भेजे जा रहे हैं। मृतकों और घायलों की पहचान से संबंधित विस्तृत जानकारी जुटाने की प्रक्रिया भी जारी है। प्रशासन की ओर से हादसे के बाद राहत एवं बचाव कार्यों को प्राथमिकता दी गई। हादसे के कारणों और संभावित लापरवाही की जांच खारड़ पुलिस ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि दोनों वाहनों की आमने-सामने टक्कर किन परिस्थितियों में हुई और क्या इसमें किसी स्तर पर लापरवाही बरती गई थी। जांच एजेंसियां ऊर्जा पार्क के भीतर वाहनों की आवाजाही, सड़क व्यवस्था और अन्य संभावित कारणों की भी पड़ताल कर सकती हैं।



भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
बेंगलुरु, 9 अक्टूबर 2026।
कर्नाटक की राजनीति में कथित रिस्टिंग ऑपरेशन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री संतोष ए.एस. ने 9 सितंबर को दक्षिण संभाग के साइबर अपराध पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

घटनाक्रम से संबंधित तस्वीरें और दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। वही, केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री से मामले की जांच कराने और आरोपों के आधार सार्वजनिक करने की मांग की है। इससे राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री का दावा मेरे पास साक्ष्य मौजूद शिवकुमार ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि कुछ लोग अलग-अलग बहानों से उनके संपर्क में आए थे। उनकी गतिविधियों पर संदेह होने के बाद उन्होंने पुलिस को सतर्क किया और संबंधित जानकारी जुटाई। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके पास इस मामले से जुड़े साक्ष्य हैं, हालांकि उन्होंने कथित साजिश में शामिल लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, उन्होंने

अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को ऐसी किसी भी गतिविधि से सावधान रहना चाहिए, जिसका उद्देश्य उन्हें किसी विवाद में फंसाना हो। हालांकि, कथित रिस्टिंग ऑपरेशन की पूरी प्रकृति और इसमें शामिल लोगों की भूमिका के संबंध में अभी तक सार्वजनिक रूप से विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। कुमारस्वामी ने उठाए सवाल, जांच की मांग केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने शिवकुमार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री के पास तस्वीरें, दस्तावेज और अन्य साक्ष्य हैं तथा पुलिस को भी इसकी जानकारी थी, तो मामले की विधिगत जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने पूछा कि कथित घटनाक्रम में शामिल लोगों की पहचान सार्वजनिक क्यों नहीं

की जा रही और अब तक क्या कार्रवाई हुई है। कुमारस्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि रिस्टिंग ऑपरेशन का मुद्रा उठाकर नाइस (NICE) परियोजना से संबंधित कथित अनियमितताओं के दस्तावेजों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। उनके इस बयान ने विवाद को एक नया राजनीतिक आयाम दे दिया है। हालांकि, ध्यान भटकाने के उनके आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप रिस्टिंग ऑपरेशन का मामला ऐसे समय सामने आया है, जब कर्नाटक में राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस विवाद में अलग-अलग नेताओं की ओर से किए जा रहे दावों और प्रत्यारोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना आवश्यक है। फिलहाल, उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर

कथित साजिश में शामिल व्यक्तियों की पहचान या आरोपों की सत्यता को अंतिम रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी मुख्यमंत्री या जनप्रतिनिधि को कथित तौर पर फंसाने का प्रयास गंभीर विषय है। ऐसे ही, यदि किसी सार्वजनिक पदाधिकारी के पास किसी षड्यंत्र से संबंधित साक्ष्य है, तो उनकी उचित जांच और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई पारदर्शिता के लिए जरूरी है। अब इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि क्या राज्य सरकार या संबंधित जांच एजेंसी औपचारिक जांच शुरू करेगी और क्या कथित साक्ष्यों को सक्षम प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही आरोपों की वास्तविकता और जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका के बारे में स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी।

लगता है मर जाऊं, मां से फोन पर कही बात, देर रात युवती ने लगा लिया फंदा, शव पोस्टमार्टम को भेजा

कानपुर: नौबस्ता थाना क्षेत्र में लंबे समय से मिर्गी की बीमारी से परेशान युवती ने पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। वह मूल रूप से गोंडा की रहने वाली थी और पिछले एक साल से अपनी बड़ी बहन के घर रहकर इलाज करा रही थी। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में बड़ी बहन के घर पर रह रही युवती ने फंदा लगाकर जान दे दी। युवती मिर्गी आने की समस्या से परेशान थी। करीब एक साल से बड़ी बहन के घर रह कर इलाज करा रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। नोट में युवती ने बीमारी से परेशान होने की बात लिखी है। पुलिस ने मोबाइल और नोट कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मूल रूप से गोंडा के सिरौटी गांव निवासी अमिता सिंह (24) एक साल से नौबस्ता हंसपुरम में अपनी विवाहित बड़ी बहन बबिता के घर पर रहकर इलाज करा रही थी। परिवजन ने बताया कि अमिता दो साल से मिर्गी की बीमारी से परेशान थी। सुसाइड नोट में परिवर्जनों से मांगी माफी है बुधवार शाम अमिता ने मां पुष्पा से फोन पर बात करते समय कहा था कि लगता है मर जाऊं। इस पर मां ने डांटते हुए ऐसे विचार मन में न लाने की बात कही थी। देर रात उसने कमरे में पंखे पर फंदा लगाकर जान दे दी। नौबस्ता इन्स्पेक्टर बहादुर सिंह ने बताया कि नोट में युवती ने माता-पिता और बहन व अन्य परिवजन से माफी मांगी है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।



भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
बेंगलुरु, 9 अक्टूबर 2026। बेंगलुरु स्थित एक निजी डीनड विश्वविद्यालय से 1.40 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। कर्नाटक साइबर कमांड ने कथित धोखाधड़ी के सिलसिले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने विश्वविद्यालय के अध्यक्ष की पहचान का दुरुपयोग कर व्हाट्सएप पर फर्जी प्रोफाइल बनाई और संस्थान के एक लेखाकार को तत्काल धन हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। इस तरीके को 'बॉस स्कैम' कहा जाता है, जिसमें ठग किसी वरिष्ठ अधिकारी की पहचान अपनाकर कर्मचारियों को वित्तीय लेन-देन के लिए गुमराह करते हैं। फर्जी व्हाट्सएप संदेश से शुरू हुई ठगी पुलिस के मुताबिक, 8 सितंबर को विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर एक

फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाई गई। इसके ज़रिए संस्थान के लेखाकार से पहले बैंक खाते में उपलब्ध राशि तत्काल निजी डीनड विश्वविद्यालय से 1.40 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। कर्नाटक साइबर कमांड ने कथित धोखाधड़ी के सिलसिले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने विश्वविद्यालय के अध्यक्ष की पहचान का दुरुपयोग कर व्हाट्सएप पर फर्जी प्रोफाइल बनाई और संस्थान के एक लेखाकार को तत्काल धन हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। इस तरीके को 'बॉस स्कैम' कहा जाता है, जिसमें ठग किसी वरिष्ठ अधिकारी की पहचान अपनाकर कर्मचारियों को वित्तीय लेन-देन के लिए गुमराह करते हैं। फर्जी व्हाट्सएप संदेश से शुरू हुई ठगी पुलिस के मुताबिक, 8 सितंबर को विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर एक



गया। संदेश को वास्तविक समझकर लेखाकार ने विश्वविद्यालय के खाते से रकम भेज दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद विश्वविद्यालय के कर्मचारी संतोष ए.एस. ने 9 सितंबर को दक्षिण संभाग के साइबर अपराध पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और वित्तीय लेन-देन की जांच शुरू की। संदिग्ध फाइल से सिस्टम तक पहुंचने का आरोप जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ठगी को अंजाम देने से पहले संस्थान के कर्मचारियों को एक ZIP फाइल भेजी गई थी। पुलिस का आरोप है कि फाइल खोलने के बाद आरोपियों ने कंप्यूटर प्रणाली तक अनधिकृत पहुंच हासिल की और क्रोम ब्राउजर के माध्यम से व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने कर्मचारियों की जानकारी के बिना संस्थान का डेटा हासिल किया और करीब 15 से 20 दिनों तक विश्वविद्यालय के वित्तीय लेन-देन पर नजर रखी। इसी जानकारी का

इस्तेमाल कर उन्होंने अध्यक्ष के नाम पर लेखाकार से संपर्क किया और रकम हस्तांतरित करवा ली। जांच में विदेशी आईपी पत्तों के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। चार गिरफ्तार, मुख्य संदिग्ध की तलाश जारी पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनैया (26), बसपल्ली रविकुमार रेड्डी (26), अंबराया (39) और सैयद वजिहद्दीन कादरी (26) के रूप में की है। ये आरोपी क्रमशः बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश और कलबुर्गी से संबंधित बताए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8.50 लाख रुपये नकद और चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में सन्नी उर्फ डेविड नामक एक अन्य संदिग्ध फरार है और उसकी तलाश का जा रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि कथित निरोह ने विभिन्न राज्यों में 22 ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में 60 से अधिक ऐसे बैंक खातों का

इस्तेमाल किया, जिनका उपयोग ठगी की रकम प्राप्त करने और आगे हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। ऐसे खातों को आम तौर पर 'म्यूल अकाउंट' कहा जाता है। इन मामलों में आरोपियों की वास्तविक भूमिका और धन के पूरे प्रवाह की जांच जारी है। संस्थानों के लिए साइबर सुरक्षा की चेतावनी यह घटना बताती है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी की तस्वीर या नाम से आया संदेश अपने आप में उसकी प्रामाणिकता का प्रमाण नहीं है। साइबर अपराधी संस्थान के आंतरिक डेटा और वित्तीय प्रक्रियाओं की जानकारी जुटाकर कर्मचारियों को जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि बड़ी रकम हस्तांतरित करने से पहले संबंधित अधिकारी से उसके पहले से सत्यापित फोन नंबर पर संपर्क कर निर्देश की पुष्टि की जाए। अनजान स्रोतों से प्राप्त ZIP फाइल

या संदिग्ध लिंक खोलने से बचना चाहिए। संस्थानों को व्हाट्सएप वेब के जुड़े उपकरणों की नियमित जांच, बहुस्तरीय सत्यापन और बड़े भुगतान के लिए दोहरे अनुमोदन की व्यवस्था भी अपनानी चाहिए। बेंगलुरु का यह मामला संगठनों के लिए चेतावनी है कि साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वित्तीय लेन-देन से जुड़े प्रत्येक कर्मचारी की सतर्कता से भी जुड़ी है। पुलिस की जांच पूरी होने और अदालत में साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही मामले के सभी पहलुओं पर अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सकेगा। समाचार आधार 9 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, कर्नाटक साइबर कमांड ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में संदिग्ध ZIP फाइल, व्हाट्सएप वेब के कथित दुरुपयोग और म्यूल बैंक खातों की भूमिका सामने आई है।